स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–3, फाल्गुन 2067, मार्च 2011

विदर्भ विशेषांक

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अनुक्रम

आवरण कथा
राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई
– डॉ. अश्विनी महाजन /4

स्वदेशी पत्रिका (विदर्भ विशेषांक)
अतिथि संपादक का मनोगत
– अजय पत्की /6

विश्लेषण
प्रचुर साधन सम्पदा के बावजूद विदर्भ पिछड़ा क्यों?
– डॉ. शरद निंबालकर /7

कार्यवृत्त
विदर्भ प्रांत में स्वदेशी जागरण मंच का कार्य (1991 से 2009 तक) – प्रा. अविनाश साकले /10

विदर्भ प्रदेश – वार्षिक कार्यवृत्त : 2010–11
– प्रा. अजय पत्की /12

नागपुर – कार्यवृत्त – आशुतोष पाठक /12

मानव सेवा : सेवाग्राम से शोधग्राम तक एक यात्रा
– पराग/अरुंधती पांढरीपांडे/23

समीक्षा : विदर्भ के औद्योगिक विकास की समीक्षा
– किशोर काले /24

दृष्टिकोण : प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्रों से विदर्भ का विकास होगा या विनाश? – धनंजय भिड़े /26

इतिहास : प्राचीन विदर्भ
– श्रीपाद केशव वितले /27

लेख : दीनदयाल किसान विकास प्रकल्प
– प्रदीप वडनेरकर /28

पर्यावरण : प्रदूषित होती जीवनदायिनी
– अमोल पुसदकर /30

प्रतिक्रिया : बजट 2011–12 में आम आदमी गायब
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /32

ढीला बजट – लेकिन सही दिशा में
– डॉ.भरत झुनझुनवाला /34

पाठकनामा/2, आंदोलन/35

पाठकनामा

हर बार की तरह आम व्यक्ति पर मार

प्रणव मुखर्जी ने इस बार जन अपेक्षा के उलट अपना बजट पेश किया। बजट भी ऐसा जिसमें टीवी, कम्प्यूटर, कारें और इलैक्ट्रॉनिक्स माल सस्ता, बाकी सब महंगा। यह बजट भी अमीरों के हितों के लिए बनाया गया है, जिसमें आम व्यक्ति को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। इस बजट से मामूली आयकर छूट के अलावा आम आदमी को मिला ही क्या। व्यापारी वर्ग को भी निराशा मिली है। वह करों में छूट चाहता था, लेकिन वित्त मंत्री ने अलग अलग तरीकों से कई और कर लाद ही दिया है। जनता को बजट या अन्य करों से कोई लेना देना नहीं। उसकी चिंता महंगाई को लेकर है। इस बजट से महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। खुद वित्त मंत्री यह मान चुके हैं। बेरोजगार नवयुवक और गरीबों को क्या मिलने वाला है? उसको तो दर–दर की ठोकरें खानी ही है।

वित्त मंत्री चाहते तो अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाते जैसे पहली कार पर सामान्य टैक्स, दूसरी कार लेने पर ज्यादा टैक्स लगाते, इसी तरह पहले मकान पर कम टैक्स, दूसरा मकान खरीदने पर ज्यादा कर। इसी तरह विलासिता सामानों पर कर अधिक करना चाहिए। परंतु वित्तमंत्री तो अमीरों के हितैषी है उन्हें गरीबों से क्या लेना–देना। खैर वक्त आ गया है कि आज भारतीय जनता सोचें कि वित्तमंत्री के भरोसे न रहकर प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर के लोगों में आपसी सहमति बनें कि कैसे इस महंगाई से पीछा छुड़ाया जाए। तभी भारत की गरीब जनता का भला होगा अन्यथा इसी तरह बजट हर साल आता रहेगा और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाएगा।

कहने को वित्त मंत्री ने किसानों को खुश करने वाला बजट पेश किया है। पर किसानों को सीधे सब्सिडी देने के एक मात्र फैसले के अलावा और क्या खास है। किसानों को निरंतर समस्यांओं का सामना कर पड़ रहा है। वे कभी खाद के लिए परेशान होते हैं तो कभी बीज के लिए। कभी उनकी फसल मारी जाती है तो कभी साहूकारों से उनका शोषण होता है। आखिर वह दिन कब आएगा जब किसानों को नियमीत आय होगी और वे किसानी को अपना रोजगार भी बना सकेंगे। सोनिया गांधी की इच्छा के अनुरूप इस बार खाद्य सुरक्षा विधेयक आने की चर्चा है, यदि यह होता है तो ही लगेगा कि सरकार गरीबों और किसानों के हित में सोंचती है।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, अभय खण्ड, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

सीवीसी की नियुक्ति के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। इस मामले में गठबंधन की कोई मजबूरी नहीं थी। मैं थॉमस की नियुक्ति को गैरकानूनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ।

– प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

बेरोजगारी तो वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की आंखों से ओझल ही हो गई। युवाओं को भी बजट से निराशा हुई है। वहीं, रसोई की मार झेल रही महिलाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

– सुषमा स्वराज

मैं भारतीय सिनेमा में किसी भी तरह के बदलाव का विरोधी हूँ। पश्चिमी सिनेमा भले ही बालीवुड की आलोचना करे, लेकिन भारतीय सिनेमा देश को एक सूत्र में पिरोए रखने का एक सशक्त माध्यम है।

– अमिताभ बच्चन

संपादकीय

न्यायालय का हंटर, दौड़ती सरकार

आम आदमी को बजट के बड़े–बड़े आंकडे समझ में नहीं आते। उसके लिये बजट उसकी आमदनी और खर्च के बीच के अन्तर का हिसाब–किताब है। बजट से पहले आम आदमी एक ऐसी सूची बनाता है जो उसकी परेशानी के कारक होते हैं और यह सोचता है कि इस सूची के अनुसार यदि वित्त मंत्री कोई प्रावधान करते हैं तो उसका जीवन थोड़ा सरल हो सकता है। नये वित्त वर्ष के लिये घोषित बजट में वह आम आदमी सूची लिये खड़े यह सोचता रहा कि आखिर उसके लिये इसमें है क्या? जो नौकरीशुदा लोग हैं उनको वित्त मंत्री ने यह बताया कि अब आयकर की सीमा 1,80,000/–रूपये कर दी गयी है। यानि लगभग 15,000 रूपया महीना कमाने वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। यही नौकरीपेशा आदमी यह सोचता रहा कि उसके लिये इसका क्या मतलब? कुल मिलाकर 2 हजार रूपये की सालाना कर छूट मिली उसके बदले सरकार उससे लेगी क्या, यह भी सवाल उसके मन में आया। बजट पर जब थोड़ा गंभीर विश्लेषण हुआ तब उस आम आदमी को यह पता चला कि वित्त मंत्री ने सांस लेने पर कर लगाने को छोड़कर कहीं कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा ही नहीं जहां वह बच सके। इस बार जिन सेवाओं पर कर लगाया गया है। वह सीधे आम आदमी पर भार बढ़ायेगा। कपड़े खरीदेगा तो उसे अतिरिक्त कर देना होगा, होटल में खाना खाने जायेगा तो उसे अतिरिक्त कर देना होगा और तो और अब उसका बीमार होना भी उसके लिये ज्यादा मंहगा पड़ेगा। भविष्य के लिये कुछ जमा करने की उसकी आदत पर भी सरकार की मार पड़ी अब बीना योजनाओं पर भी सेवाकर लाद दिया गया है। पहले से ही महंगाई का दंश झेल रहा आम आदमी यह सोचता रह गया कि आखिर सरकार से कोई राहत उसे मिलेगी या नहीं। जब कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से यह सवाल पूछा कि आपका यह बजट क्या महंगाई को और नहीं बढ़ायेगा तो उन्होंने झेंपते हुए कहा कि ज्यादा नहीं थोड़ी महंगाई बढेगी। इस थोड़ी की परिभाषा सरकार देना नहीं चाहती, हां मंहगाई बढ़ाने की अपनी हवस को वित्त मंत्री ने विकास के मुद्दे से जोड़ दिया और उन्होंने लोगों को समझाया कि 8 फीसदी विकास दर को बनाये रखने के लिये आम आदमी को थोड़ा और मरना चाहिए, उन्होंने कहा कि मंहगाई की सूचक मुद्रास्फीति की दर कम तो की जा सकती है लेकिन इससे विकास पर असर पड़ेगा। कोई इनसे पूछे कि देश में विकास सिर्फ बड़े लोगों के लिये है, केवल कंपनियों को या औद्योगिक घरानों को ही जीने का अधिकार है। आम आदमी इस विकास में कहीं मायने रखता है या नहीं।

अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेचारगी के शिकार हैं। लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, कभी घोटाले को लेकर तो कभी अनैतिकता को लेकर। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार पर ऐसी–ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन्हें किसी भी प्रधानमंत्री के लिये एक शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। बोफोर्स, काले धन, सीवीसी की नियुक्ति और टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला जैसे मामलों में सरकार की एक बार नहीं कई बार छीछालेदार हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कहा कि "What the hell is going on" इसका हिन्दी में आशय है कि सरकार ने क्या नर्क मचा रखा है। यह टिप्पणी काले धन के मामले में आरोपी हसन अली खां के प्रति सरकार के नरम रवैये पर की गयी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री को यह बताने पर विवश हो गया है कि देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार क्या करेगी। यह किसी भी सरकार के लिये शुभ लक्षण नहीं हैं। पर प्रधानमंत्री पर इसका असर नहीं है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उनके दामन पर एक और दाग जड़ दिया है। नैतिकता का तकाज़ा यह था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस मसले पर देश से माफी मांगती, पर प्रधानमंत्री यहां भी अपनी बेचारगी दर्शा गये। उनका यह कहना कि कार्मिक विभाग के राज्यमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी उन्हें नहीं दी थी, यह दर्शाता है कि सरकार में ही प्रधानमंत्री की स्थिति कितनी कमजोर है। उनके अधीन काम करने वाला एक नेता ऐसी सूचनायें दबाकर रख सकता है जो बाद में सरकार और संविधान के माथे पर कलंक साबित हो सकती है और उस नेता को कांग्रेस नेतृत्व इनाम देकर महाराष्ट्र जैसे बड़े राष्ट्र का मुख्यमंत्री पद भेंट कर सकता है।

हसन अली गिरफ्तार हो गया। उसकी तमाम गैर कानूनी एवं देश विरोधी गतिविधियों की अब जांच शुरू हो गयी है। प्रवर्तन निदेशालय के पास अब उसके खिलाफ दस्तावेज़ भी मिल गये हैं। पर देश को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार किन कारणों से हसन अली के प्रति अब तक नरम बनी रही। अगर सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं देता तो सरकार को उसकी गिरफ्तारी के लिये नहीं झकझोरता, तो अब तक हसन अली देश की व्यवस्था को मुंह चिड़ाता रहता। सरकार के पास 2008 में ही इस बात की ठोस सूचना आ गयी थी कि इस व्यक्ति ने हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं के व्यापार और आतंकवादियों को सहायता देकर 35 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक का काला धन इकट्ठा कर रखा है। उसने यह रूपये रिवस बैंक के एक खाते में जमा कर रखा है, इसकी खबर भी सरकारी विभागों के पास थी लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण सरकारी विभाग आंखें बंद किये रहे। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने हसन अली के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामलों में चलाने की सलाह दी है, तब जाकर इन विभागों में हरकत शुरू हुई है। अब देखना यह है कि देश का पैसा हसन अली जैसे शातिर अपराधियों की तिजोरी से बाहर आता है या नहीं।

आवरण कथा

राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली अनावश्क छूटों को समाप्त किया जाए और इस प्रकार से राजस्व में होने वाले घाटे को दूर किया जाए। ऐसा होने पर ही देश मंहगाई डायन से बचकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ पायेगा।

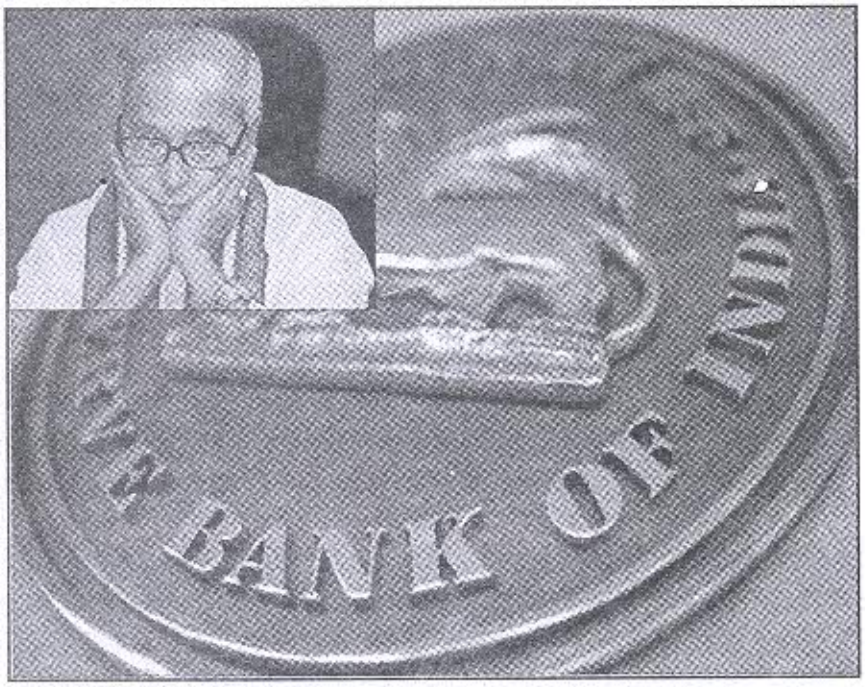

अधिक कर्ज उठाने से भविष्य के लिए सरकार की देनदारियां बढ़ जाती है और उसे बढ़े हुए कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। पिछले कुछ समय से सरकार के कुल बजट का 20 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज की अदायगी में ही चुक जाता है, जिसके कारण सरकार सामाजिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और विकास के लिए अन्य जरूरी मदों पर खर्च नहीं बढ़ा पाती।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

वित्त मंत्री जब आगामी वर्ष 2011–12 का बजट संसद में पेश कर रहे थे, तो जो यह समाचार फ्लैश हुआ कि वर्ष 2010–11 के लिए बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.5 प्रतिशत रखा गया था, वह संशोधित अनुमानों के अनुसार घट कर 5.1 प्रतिशत ही रह गया है। यह देश के लिए एक सुखद् समाचार था। यह हम सब जानते है कि जब सरकार अपनी आमदनी से अधिक खर्च करती है तो उससे राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो बाजार से कर्ज उठाती है या भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज के माध्यम से देश में अतिरिक्त कैरेंसी छापी जाती है। अधिक कर्ज उठाने से भविष्य के लिए सरकार की देनदारियां बढ़ जाती है और उसे बढ़े हुए कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। पिछले कुछ समय से सरकार के कुल बजट का 20 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज की अदायगी में ही चुक जाता है, जिसके कारण सरकार सामाजिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और विकास के लिए अन्य जरूरी मदों पर खर्च नहीं बढ़ा पाती। यदि सरकार इस राजकोषीय घाटे की भरपाई अधिक नोट छापकर करती है, तो उससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है। दोनों ही प्रकार से राजकोषीय घाटा बढ़ने पर देश का विकास तो बाधित तो होता ही है, आम जन के लिए कठिनाईयां बढ़ जाती है। ऐसे में जब यह समाचार आया कि राजकोषीय घाटा सिमट कर 5.1 प्रतिशत ही रह गया है, तो शेयर बाजारों ने इसका जोशो–खरोश के साथ स्वागत किया और मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 600 अंक बढ़ गया, लेकिन जब बजट आंकड़े आने पर सच्चाई सामने आ गयी और उसी दिन बाजार के बंद होने तक वह संवेदी सूचकांक 480 अंक नीचे आ गया।

एफ.आर.बी.एम एक्ट और राजकोषीय घाटा

कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने एफ.आर.बी.एम. कानून पास करते हुए स्वयं पर यह अंकुश लगाया था कि राजकोषीय घाटे को कम करते हुए उसे तीन वर्षों में 2.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने इस संकल्प पर अडिग न रह सकी और अपने ही संकल्प की धज्जियां उड़ाते हुए वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटे को लगभग 7 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया। सरकार ने इसके लिए यह तर्क

दिया कि वैश्विक मंदी से उबरने के लिए सरकार को एक ओर करों में छूट देनी पड़ी और दूसरी ओर सरकारी व्यय बढ़ाना पड़ा। वित्त मंत्री का कहना है कि अब बदली हुई परिस्थितियों में सरकार एफ. आर.बी.एम. एक्ट के अनुरूप अपने राजकोषीय घाटे को कम करके उसे 2.5 प्रतिशत पर लाने के लिए संकल्पित है। इसके लिए वित्त मंत्री ने यह कहा कि वर्ष 2010–11 में संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 5.1 प्रतिशत ही रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार के इस दावे से सहमत नहीं है।

राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई

हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह बजट अनुमानों में 5.5 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत लाया गया है, लेकिन यदि हम बजट आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि वर्ष 2010–11 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 3,81,408 करोड़ रूपये रखा गया था, संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा 4,00,998 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, यानि लगभग 20 हजार करोड़ रूपये अधिक। ऐसे में राजकोषीय घाटा कम कैसे हुआ यह समझ से परे है। आंकड़ों की कारीगरी के माध्यम से ही इस बढ़े हुए राजकोषीय घाटे को कम दिखलाया जा सकता है।

सरकारी हलकों में यह बात कही जा रही है कि राजकोषीय घाटे को कम दिखाने में मुद्रा स्फीति (महंगाई) ने सरकार को मदद की है। इस बात को समझने के लिए हम आंकड़ों का ही उपयोग करते हैं। सीएसओ के 2010–11 के जीडीपी के अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2010–11 में जीडीपी की संवृद्धि दर 19 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी की संवृद्धि दर मात्र 9 प्रतिशत ही है। विडंबना यह है कि राजकोषीय घाटे को चालू कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही आंका जाता है। ऐसे में चालू कीमतों पर 19 प्रतिशत बढ़ी हुई जीडीपी के कारण राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत ही दिखाई देता है। हम कल्पना करें कि महंगाई यदि 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत होती तो राजकोषीय घाटा मात्र 4.2 प्रतिशत ही दिखाई देता। इसका मतलब यह नहीं है कि राजकोषीय घाटा कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि मंहगाई के कारण राजकोषीय घाटा कम दिखाई दे रहा है।

वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6 प्रतिशत ही रहेगा। यदि हम इसे नजदीक से देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के तुलना में वर्ष 2011–12 का राजकोषीय घाटा लगभग 31,000 हजार करोड़ रूपये अधिक है। चाहे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसके 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत तक घटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यदि इस वर्ष के बजट घाटे और सरकारी दावों का निकटता से अध्ययन किया जाए तो निम्नलिखित बातों पर गौर करना जरूरी होगा –

पिछले लगभग एक वर्ष से खाद्य सुरक्षा कानून बनाने और उसे लागू करने की कवायद चल रही है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पुनः इस बात को दोहराया कि सरकार खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पेश करेगी। हालांकि सरकार स्वयं भी खाद्य सुरक्षा कानुन के बारे में अधिक उत्साह नहीं दिखा रही, फिर भी यदि इस कानून को लागू किया जाता है तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रूपये हर वर्ष इस पर खर्च होगें। लेकिन विडंबना यह है कि बजट में इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि यह कानुन बनता है तो राजकोषीय घाटे में और वृद्धि संभव है।

हर वर्ष रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विस्तार हेतु पहले से अधिक धन आवंटित किया जाता रहा है। इस वर्ष हालांकि मजदूरी दर में वृद्धि करने की बात की गई है, लेकिन इस हेतु बजट में प्रावधान दिखाई नहीं देते हैं।

इस वर्ष सब्सिडी बिल में 20,000 करोड़ रूपये की भारी कटौती भी की गई है। संभव है कि परिस्थितियों के अनुरूप इस कटौती को अंजाम देना संभव न हो। ऐसे में राजकोषीय घाटा और भी बढ़ सकता है।

इन सब कारणों से सरकार के वे समस्त दावे कि राजकोषीय घाटा कम होने से महंगाई पर लगाम कसी जा सकेगी, निजी निवेष को बढ़ावा मिलेगा और देश सरपट विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पायेगा, तर्कहीन जान पड़ते है। ध्यातव्य है कि कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली छूटों के कारण हर वर्ष बजट में राजकोष का नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। वर्ष 2010–11 में यह नुकसान 511630 करोड़ रूपये रहेगा जबकि वर्ष 2009–10 में यह 482432 करोड़ रूपये था। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली अनावश्क छूटों को समाप्त किया जाए और इस प्रकार से राजस्व में होने वाले घाटे को दूर किया जाए। ऐसा होने पर ही देश महंगाई डायन से बचकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ पायेगा। ❑

:: अतिथि संपादक का मनोगत ::

प्रतिमाह प्रकाशित होने वाली स्वदेशी पत्रिका पाठकों को वौद्धिक सामग्री प्रदान करने वाला प्रभावी उपकरण है। देश के ख्यातनाम चिंतक, लेखक, अर्थशास्त्री पत्रिका में लिखते हैं। इसका उपयोग सभी कार्यकर्ताओं को अपनी प्रेरणा बनाएं रखने के लिए तथा कार्यप्रवण रहने के लिए होता रहता है। साथ ही देश की गतिविधियों के बारे में प्रत्यक्ष कार्यरत व्यक्तियों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है।

गत कई वर्षों से पत्रिका का शुल्क भरना तथा आए हुए लेखों को पढ़ना यह क्रम जारी रहा। दो वर्ष पूर्व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक मा. श्री कश्मीरीलालजी ने प्रांत संयोजकों की बैठक में एक विषय रखा। प्रत्येक प्रांत का, स्वदेशी पत्रिका के विकास में योगदान होना चाहिए। इस विकास के कई आयाम हो सकते है। श्री कश्मीरीलालजी ने अपनी विशिष्ट शैली में कार्यकर्ताओं से ऐसे आयामों की चर्चा की। प्रस्तुति का स्वरूप, विज्ञापन, आर्थिक पक्ष, संपादन, समाज के समविचारी तथा आर्थिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में स्वदेशी पत्रिका का प्रसार आदि तथा अन्य पक्ष भी चर्चा में सम्मिलित रहे। श्री कश्मीरीलालजी की चर्चा ने सभी प्रांत संयोजकों को उनके अपने प्रांत का पत्रिका संचालन में नगण्य योगदान है इसका अहसास कराया। सभी ने स्वयं होकर स्वीकार किया कि अपने–अपने प्रांत की विशेषताओं को उजागर करनेवाला तथा प्रांत का सर्वस्पर्शी परिचय कराने वाला विशेषांक निकाला जाए। विदर्भ विशेषांक भी इसकी एक कड़ी है। स्वदेशी जागरण मंच ने जून 2010 में रायपूर में आयोजित राष्ट्रीय परिषद् में राजकीय दृष्टि से संचालित संपूर्ण महाराष्ट्र को एक प्रांत करने की घोषणा की। इसके पूर्व स्वदेशी जागरण मंच की व्यवस्था से महाराष्ट्र में विदर्भ, देवगिरी, कोंकण तथा पश्चिम महाराष्ट्र ऐसे कुल 4 प्रांत थे। अब इन चारों को मिला दिया गया हैं किंतु विदर्भ विशेषांक की घोषणा इस सम्मिलीकरण के पूर्व ही हुई थी, इसलिए यह अंक भले ही विलंब से किंतु पूर्व निर्धारण निर्णय के अनुसार अपने समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है क्योंकि यह अपने आपमें एक अनूठा एवं इस प्रकार का पहला ही प्रयास है।

इस अंक में विदर्भ के महापुरुषों की जानकारी, विदर्भ की ताकत एवं कमजोरियां, जंगल, पर्यावरण, नदियां, प्रचुर खनिज उपज आदि के बारे में तथा प्रांत का स्वदेशी संबंधित गत कुछ महिनों का कार्यवृत्त तथा छायाचित्र इनकी प्रस्तुति की गई है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समृद्धि के पश्चात् विदर्भ पिछड़ा क्यों रहा है यह सभी का सदा से ही चिंता एवं चर्चा का विषय रहा है। विदर्भ के यवतमाल, वर्धा जिले केवल देश में ही नहीं अपितु संसार में किसानों की आत्महत्याओं के लिए चर्चित है। सामाजिक संस्थाओं की ओर से इस जटिल समस्या के निदान में कुछ कार्य किया गया है, उसे भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

विशेषांक प्रकाशित करने के लिए आवश्यक अनुभव, साधन, लेखन कार्य में अरुचि जैसे अभाव बड़ी मात्रा में ध्यान में आए हैं। विशेषांक के इस उपक्रम के कारण स्वदेशी जागरण कार्य के लिए समाज में कार्यरत सभी प्रकार के लोगों से संबंध प्रस्थापित करना कितना आवश्यक है इसका भी अनुभव हुआ है। इन सभी अभावों के होते हुए भी जिन लेखकों व विज्ञापनदाताओं ने इस कार्य को संपन्न करने में अपना सहयोग दिया है उनका हृदय से आभार।

अजय पत्की
संयोजक, महाराष्ट्र प्रांत